The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 ? under Consideration

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री नित्यानन्द राय):** माननीय सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से यह प्रस्ताव* करता हूं

?कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । ?

माननीय सभापति **:** आप इस विधेयक पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए ।

श्री नित्यानन्द राय**:** सभापति महोदय, भारत विभिन्न प्रकार की आपदाओं को झेलता है । भारत के लगभग सभी हिस्सों में किसी भी मौसम में आपदाएं आती रहती हैं, यह भारत ने देखा है । वर्ष 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विकसित भारत बनाना है । उस संकल्प को पूरा करने के लिए ?जीरो कैजुअल्टी एप्रोच? की नीति के साथ सरकार काम कर रही है ।

आपदाओं से काफी नुकसान होता है लेकिन यह सच है कि गत वर्षों में जब से माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, कुशल आपदा प्रबंधन के कारण नुकसान में काफी कमी आई है । जान-मान के नुकसान को देखें तो सुपर साइक्लोन में जहां 10,000 लोगों की जानें गई थीं, वहां ?बीपरजॉय? और ?दाना? में जीरो मानवीय क्षति हुई ।

महोदय, वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया और इसके क्रियान्वयन में राज्यों को कई बाधाएं और कठिनाइयां महसूस हुईं । उन बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई राज्यों ने गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया । आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यकारी समितियों के बीच प्रभावी कार्यात्मक एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई जिसके कारणवश माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस सदन में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2024 लेकर आए ।

महोदय, इस संशोधन विधेयक के कुछ उद्देश्य हैं, मैं इनके बारे में माननीय सदन को जरूर बताना चाहूंगा । आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राधिकरण और समितियों की भूमिकाओं में और अधिक स्पष्टता एवं कन्वर्जेंस लाने के लिए यह विधेयक जरूरी है । राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय समिति और अधिनियम पूर्व कतिपय संगठनों को वैधानिक स्टेटस प्रदान करना भी इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य है । इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के दक्ष कार्यकरण को सुदृढ़ करना है । इस संशोधन विधेयक के और मुख्य उद्देश्य हैं - राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटा बेस सृजित करने का उपबंध करना, राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों, जिनमें नगर निगम है, के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का उपबंध करना और राज्य सरकार द्वारा राहत आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का उपबंध करना ।

महोदय, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं, उनके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं लेकिन राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा कुछ कमियां महसूस की गई हैं इसलिए यह

संशोधन विधेयक लाना आवश्यक है । भारत सरकार को महसूस हुआ कि इस विधेयक को लाकर कमियों को दूर कर सकते हैं और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ कर सकते हैं । विगत कई वर्षों में, खासकर वर्ष 2014 के बाद आपदा प्रबंधन के तहत उठाए गए कदमों के बारे में मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं । माननीय गृह मंत्री जी माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो परिणाम आए हैं, मैं संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा ।

महोदय, वर्ष 2016 में एनडीए द्वारा पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाएं विकसित की गईं और इन योजनाओं की पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई सम्मेलनों के माध्यम से सराहना की गई है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2016 में एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान डीआरआर पर 10-सूत्री एजेंडा जारी किया ।

यह आज दुनिया भर में आपदा के क्षेत्र में एक सूत्र बन गया है । वर्ष 2019 में सीडीआरआई का शुभारंभ हुआ । अब तक 40 देश और 7 अन्य संगठन इसके सदस्य बन चुके हैं । 350 जिलों में एक लाख स्वयंसेवी आपदा मित्र को प्रशिक्षित कर तैनात किया गया है । एनडीआरएफ में चार बटालियनों को बढ़ाया गया है । कुल बटालियन अब 16 हैं । चक्रवात के लिए सामान्य एलर्ट प्रोटोकॉल योजना के माध्यम से तत्काल एलर्ट किया जाता है । वर्षा और बांध एवं नदियों के जलस्तर पर एवं सभी आपदाओं के पूर्वानुमान पर पूर्व चेतावनी पहले 3 दिन हुआ करती थी, अब वह 7 दिन हो गई है । 7 दिन पूर्व ही हम चेतावनी दे देते हैं । राष्ट्रीय चक्रवात से बचाव हेतु शमन परियोजना के अंतर्गत तटीय राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित की गई हैं ।

माननीय गृह मंत्री जी ने वर्ष 2019 में एक बड़ा निर्णय लिया । पहले जब कोई आपदा आती थी, तो जब तक वहां से आवेदन नहीं आता था, तब तक कोई टीम असेसमेंट के लिए नहीं जाती थी । अब आईएमसी टीम पूर्व में ही जाती है । हम राज्यों को सूचित करते हैं । राज्य उस सूचना का संज्ञान लेकर जब हमें सूचित करता है, तो हम जाते हैं । हम उनके आवेदन का, अनुरोध का इंतजार नहीं करते । चक्रवात जोखिम शमन और मोचन हेतु डीसीआरए और डीएसएस टूल विकसित किया गया है । राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों का मानचित्र तैयार किया गया है ।

भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा डिजिटल एटलस विकसित किया गया है । हिमालय के क्षेत्र में 28 हजार हिमनद झीलों का व्यापक डेटा तैयार किया गया है । इसका परिणाम यह है कि सुपर साइक्लॉन में 10 हजार मौतें हुईं, जबकि बिपरजॉय और दाना में जीरो कैजुअलिटीज हुई हैं ।

महोदय, लू से वर्ष 2015 से ठीक पहले 2 हजार 40 लोगों की जानें गई थीं, जो वर्ष 2024 में घटकर 244 हो गई हैं । एनडीआरएफ ने भी अपने ऑपरेशन के माध्यम से बहुत लोगों की जान बचाई है । आईएमडी का सटीक मौसम पूर्वानुमान आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आज बहुत उपयोगी है । हम उस नुकसान के पूर्वानुमान के आधार पर सजग होकर तैयारी करते हैं । आपदा रिस्पांस के संसाधनों की इन्वेंट्री का डेटाबेस आईडीआरएन तैयार किया गया है । एकल आपातकालीन नंबर 112 के साथ ईआरएसएस का विस्तार हुआ है । आंकड़े एकत्र करने और डीआरआर के लिए नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का विकास हुआ है । इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड द इंस्टीट्यूशन्स नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना हुई है । अब तक 318 संस्थान इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं ।

एनडीआरएफ द्वारा स्कूलों में सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । क्षेत्रीय संगठनों जैसे एससीओ, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल, बिम्सटेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के तहत आपदा प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा है । राज्य सरकारों को वर्ष 2015-20 की तुलना में वर्ष 2021-26 में एसडीआरएफ के आवंटन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है ।

एसडीआरएफ के आवंटन में 109 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि की गई है । देश में पहली बार वर्ष 2021 में नैशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के मध्य एसडीआरएफ में मात्र 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था ।

<u>15.00 hrs</u>

जो वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक तीन गुना बढ़कर 1,24,000 करोड़ रुपये हो गया है । एनडीआरएफ को भी वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच 28,000 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जो वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक तीन गुना बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये हो गया है । इस प्रकार देखा जाए तो इन दस वर्षों में जारी की गई राशि में तीन गुना की वृद्धि हुई है ।

महोदय, मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि वर्ष 2047 तक भारत को ?विकसित भारत? बनाने का संकल्प लिया गया है और यह विधेयक आज के समय की जरूरत है । इसमें सभी मॉडर्न डायनामिक्स परिभाषित किए गए हैं ।

इस विधेयक के पारित होने के साथ ही, जो भी प्रभावित लोग हैं, आपदा के कुशल प्रबंधन से निश्चित रूप से उस क्षेत्र में इतनी कामयाबी हासिल होगी कि हम नुकसान को कम कर पाएंगे और जान-माल के नुकसान को भी कम कर पाएंगे । इसलिए, इस विधेयक को लाना जरूरी था । माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदाओं से प्रभावित उन लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा है । माननीय गृह मंत्री जी यह विधेयक लेकर आए हैं । हम सदन से आग्रह करेंगे कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए । धन्यवाद ।

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

Hon. Members, it is an important Amendment Bill regarding Disaster Management. So, I would request all the Members to be present here and give their important views.

Now, I would request Dr. Shashi Tharoor to initiate the discussion.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Chairman.

I rise today in opposition to the Disaster Management (Amendment) Bill 2024 moved by the hon. Minister because it is a disaster. I would like to elucidate our perspective on the legislation. We had great expectations of it, but it appears to have been taken out of the oven half-baked and rushed into this hallowed chamber clamouring to be passed. That this Bill is even being debated in the Parliament is miraculous because several of my colleagues in the Opposition pointed out on the 1st August 2024, when the hon. Minister of State introduced this Bill, that this legislation was brought under Entry 23 of the Concurrent List of the Constitution.

Mr. Chairman, you do not have to be a Constitutional expert to realise that social security and social insurance, employment and unemployment, which are subjects of Entry 23 do not even remotely cover Disaster Management. Now, the matter that had the Government actually try legislating on the issue of unemployment, unemployment in India might not be in such disastrous shape but चलो, कोई बात नहीं, चलेंगे । We will carry on.

But anyway, here we are with a Bill hurried into the Parliament on a constitutionally untenable and federally unviable ground and with a host of other drawbacks that diminish even the little imagination that the Centre has sought to display.

Now, before the Treasury Benches accuse the Opposition of opposing just for the sake of it, let me reassure them that I find myself in agreement with the rationale for this Bill that the Minister has just explained. In my first Parliamentary term, I was the Convenor of the Parliamentary Forum on Disaster Management which has since been abolished by the NDA Government. Yes, the Disaster Management Act of 2005 was in need of rigorous reform. And yes, there is a pressing need to streamline our sprawling and scattered disaster management framework which, despite the best of intentions, ends up causing inordinate delays in the worst moments failing to rescue our fellow Indians caught up in disasters.

Now, we see and he is right to say human lives, infrastructure, mother nature and all of these things are affected by disasters. But we, as MPs from Kerala, understand this very well. Yet, far from strengthening and making effective our crisis management mechanisms and far from bringing, as the Minister just promised, more clarity and convergence to our prevailing disaster management instruments and institutions, it actually exacerbates the problem. Sadly enough, it was an ill-thought-out, overlapping and convoluted distribution of powers amongst the authorities and committees, and it envisages or retains from the current Act. The net result is a greater centralisation of the Disaster Management Act, 2005 and a top-down approach that would create a chain of command so complicated and heavy that it may collapse under its own weight before even mitigating, much less preventing, any horrific disaster like the landslides in Wayanad, which were the most devastating landslides in Kerala?s history.

On the 3rd of August, Mr. Chairman, after my hon. colleague from Wayanad visited, I made an emotionally crushing visit to Wayanad and assisted in the distribution of relief supplies gathered by the MP office in my constituency of Thiruvananthapuram. Picking my way through the rubble to view the destruction of

Mundakkai, Chooralmala, and Punchiri Mattam, I beheld massive JCBs rumbling, where, till five days previously lavishly green hilly villages had sprawled beneath great blue skies. At a hospital suffused with the anguish of countless Indians, whose homes and dreams were pulverized by bombardment of rocks and boulders, in the early hours of 30th July, I met a young survivor who had endured inconceivable horrors, just eight years old. She had lost her father, mother, brother, sister, grandfather, and grandmother, and sustained numerous injuries from broken bones to a heavily bruised face. As I saw her propped up in bed, immersed in a colouring book, desolation gripped me. We should have been able to prevent, to predict better what was to come, prepare for it, and even to prevent it. But we failed at all of these. The wails of Wayanad and the scenes of devastation and despair that greeted me there and my colleagues who have been there, and in the relief camps, will forever haunt me.

All of us together owed it to the more than 480 people who perished in Wayanad, and an equally staggering number who were grievously injured, to ensure that no Indian citizen in any part of our country ever again has to endure such a gruesome fate. But this Bill, I am afraid, does not guarantee that. Right off the bat, this Bill promises, as I mentioned, greater clarity and convergence in the roles of authorities and committees working in the field of disaster management. But in reality, it confuses and complicates and typically just concentrates power in the hands of the Central Government. This is evident when the Bill accords statutory status to the National Crisis Management Committee and the High-Level Committee, both of which predate this Bill, but without explaining why. Pursuant to clause 6, the Cabinet Secretary will chair the National Crisis Management Committee, with the Central Government deciding everything, who will be part of it, who will be invited to participate in its meetings, what powers it will exercise, the functions it will perform, and even what procedures it will follow in exercise of the power and discharge of its functions. In other words, though on paper it will be the nodal body to deal with major disasters, in reality it will be a creature of the Central Government, a timid creature. Nowhere does the Government stipulate that such a crucial body should necessarily have ecologists, environmentalists, experts of various kinds who can help us predict, prevent, prepare for, and mitigate natural disasters. This disdain for expertise is a recurring theme of this Bill.

Now, given that we already have a National Executive Committee, which is empowered to act as a coordinating body, a National Disaster Response Force for targeted responses and the overarching National Disaster Management Authority,

what is the utility of this Committee? Will it not just serve to convolute the chain of command; to delay response time in situations where tardiness can result in the loss of tens of thousands of lives? Further complicating the chain of command and vesting yet more powers on the Central Government is this: Pursuant to Section 8(b) of this revised Act, the Centre is to constitute a high-level committee with a Union Minister as Chairperson for approving financial assistance under sections 46 and 47, the National Disaster Response Fund, and the Mitigation Fund. Now, ultimately both these funds shall be applied in accordance with the guidelines laid down by the Central Government in consultation with the NDMA. So, there is no autonomy to this high-level committee. So, once again the question arises, what exactly shall be the powers of the statutory body? This Bill institutionalizes inadequacies and inefficiencies, especially at the Central Government level. Whereas pre-existing bodies with functions not clearly demarcated, overlapping with those of other institutions, have been given statutory recognition, the National Disaster Management Authority, the national linchpin of this Act, remains enslaved to the Ministry of Home Affairs and has no administrative or financial powers of its own, having to route even its minutest decisions through the Home Ministry, a needlessly arduous and time-consuming process. It has also been reported in the media that the NDMA is massively understaffed. I was hoping the hon. Minister would address that in his reply at least, if he has not done so in his introduction.

It has to stop somewhere and for better coordination of disaster management and mitigation efforts, the NDMA should have been upgraded to a Department of the Government of India, even if not to a Ministry, but it remains subordinate to the Home Ministry. Even the question of its leadership has not been satisfactorily addressed. It is officially chaired by the Prime Minister. NDMA is normally overseen by a Vice Chairperson, who has the rank of a Union Cabinet Minister, but bafflingly, clause 3 of this Bill says, ?any member of the NDMA is authorized to perform the day-to-day functions of the Authority?, forgetting that the political heft of a Ministerial rank is vital for dealing with the States and other Ministries and Departments of the Union.

Mr. Chairman, this Bill, in its ostensible pursuit to decentralise the decision-making process regarding funds manages to do something utterly bizarre. It dilutes the entire purpose of the National Disaster Response Fund by removing the specific uses for which the fund was intended. One of the most pressing criticisms of the old Act was the excessive centralisation of fund allocation. Many of our States have complained about this, especially when disasters are categorised as "severe?. The

debilitating human cost of such a disaster demands from the Centre a sense of urgency, completely absent in the proposed framework. The Centre is bereft of this sense of urgency, let alone of any compassion. It has been proved very often, especially when disaster relief funds from the NDRF were callously denied to Tamil Nadu and only disbursed to Karnataka only after an inordinate delay.

In 2023, when Tamil Nadu and Karnataka found themselves on the brink of catastrophe, they were compelled to move the Supreme Court to access the much-needed NDRF funds, funds they had a rightful claim to. ? (*Interruptions*) Yes, Himachal has been mentioned. Others, I am sure, will do so. Let me speak of the cases I know. In Karnataka, 196 out of 236 taluks had been officially designated as "severely drought-affected" by the Inter-Ministerial Central Team with the Sub-Committee of the National Executive Committee even recommending financial aid for the State, but despite this, the Congress-ruled State, I admit, had to wait over six months to receive the funds, long after the prescribed one-month period following the IMCT report. This deplorable delay deprived the State of the essential resources to protect its citizens, and frankly violated the Fundamental Right to Life of the people of Karnataka. Tamil Nadu suffered a similar fate as well, especially in the aftermath of Cyclone Michaung, when there was a dearth of necessary funds and the Central Government was indifferent.

While we in Kerala had long been demanding that the Wayanad landslide be declared a "national disaster," this request was dismissed in a letter to me by the MoS Home on the 10th of November claiming that there were sufficient funds in the State Disaster Relief Fund. The justification provided was that the existing guidelines under the SDRF and NDRF offer no provisions for such a declaration. The lack of financial aid from the NDRF, under the perversely misguided assumption that the SDRF funds would suffice, has left us in an unenviable position. With no interim aid forthcoming, Kerala has been left with no option but to insist on the declaration of the landslide as a Level-3 disaster which will at least allow us for the mobilisation of some resources and support. But many of us had raised this much earlier. No sooner had the landslides ravaged Wayanad, I wrote to the hon. Home Minister on the 31st of July, requesting him to recognise this monumental cataclysm as a "calamity of severe nature" in terms of Paragraph 8.1 of the MPLADS guidelines, so we could have all helped at that time. We could have recommended works up to a crore of rupees from the MPLADS funds, but the request was ignored. The Minister of State wrote to me in early November to tell me that an Inter-Ministerial Central Team (IMCT) had visited Wayanad from 8th to 10th of

August, and the Central Government would take action based on its request. They are supposed to take action within one month, according to the existing Act. To this date, no action has been taken and no additional funds have been arranged for Wayanad. How can we accept this?

This Bill, Sir, is an excellent case of minimum decentralisation, maximum declamation, at which, of course, this Government excels. Indeed, even one of this Bill's better provisions is undermined by the Government's refusal to walk the talk. I refer to the creation of separate Urban Disaster Management Authorities in State capitals and cities with municipal corporations, except Delhi and Chandigarh. This has been introduced to foster greater coordination than what is possible under the Disaster Management Authorities in our big urban centres. But even while it takes a step, which otherwise I would have applauded, the Centre fails to provide any necessary financial devolution.

Without it, this measure will be toothless. While the Government appears to have recognised that district administrations across India should tackle emerging threats on their own terms and in line with local conditions, it has overlooked the dismal fact that in our country the total municipal expenditure accounts for barely 0.79 percent of the GDP. Where is the money? Given that this Bill focuses on disaster risk reduction rather than post-disaster management, it is crucial that the Government realise that urban local bodies need to be financially empowered, as in other countries, to amass resources to institute, equip, and run Urban Disaster Management Authorities and discharge their risk reduction obligations to the letter. For risk reduction activities to be conducted at the local level, the creation of infrastructure that bolsters the vitality and vigour of urban local bodies is vital. But this Bill is silent on this issue, offering no real resources to revitalise India?s urban local bodies. Creation of these bodies could have been a good step towards sustainable urban spaces, but it will be useless without effective devolution of finances and authority. This half-baked provision needs to be amended.

Another damaging aspect of this Bill is that it seeks to weaken the National Executive Committee and the State Executive Committees which are staffed to the level of Secretaries to the Governments of India and the States which are supposed to formulate national-level and State-level disaster management plans. If this Bill passes, the NDMA and the SDMAs will instead assume this power. At the same time, these Committees will remain the coordinating bodies for relief, rehabilitation, and reconstruction during and after natural disasters, saddling them

in effect with the responsibility for exercising disaster management plans that they did not formulate. You execute something that you did not actually come up with. This flies in the face of the complete logic of the original purpose of these Committees which was to foster greater collaboration amongst various Ministries of the Union and the State Governments. Where is cooperative federalism here? The Bill?s major weakness has throughout been its inability to innovate on institutional mechanisms to deal with disaster risk. Although it achieves coordination for greater risk management, it offers no clarity on how to achieve such coordination in practice amongst a wide range of institutions, split both vertically and horizontally, and including non-Government, private, and civil society elements.

By the way, Mr. Chairperson, the Minister has not noted this. Disaster relief, rehabilitation, and reconstruction is still not a justiciable right in India. The Indian State has for far too long undertaken relief measures as an obligation, not a duty. It must discharge that duty in fulfilment of its citizens? inviolable rights. This has been an issue for years. But the Bill would have been an opportunity to fix it because we are learning lessons from what has not worked in the earlier version. You have been stretched. You will, of course, carry out relief assistance up to your whims and your political expediency. You may provide *ex-gratia* compensation. You may provide relief items, compensation for destruction of houses, destruction of boats, fishing equipment, farming equipment, etc. But all of this will vary from place to place. It must change. Disaster relief must be a fundamental right of all Indian citizens.

It is also important to point out one important negative factor of this Bill that testifies to its lack of imagination, creativity, and reluctance to accept the bleak realities of our environment. On 25th of July, the hon. Minister of State for Science, Technology and Earth Sciences told this House that the Government has no plans to classify coastal erosion or heat waves as notified disasters under the Disaster Management Act, 2005. This is crazy. We need to expand the list of notified disasters. Given our own experience, since the Act was passed in 2005, to this day, the disasters eligible for assistance under the NDRF remain limited to cyclones, floods, droughts, earthquakes, landslides, and so on. Coastal erosion and heatwaves are conspicuously absent. This narrow, outdated definition of ?disaster? stands in contrast to the growing global consensus that recognises coastal erosion and heatwaves as climate-related disasters.

The devastating impacts of these calamities on eco-system, on human health, are no longer matters of debate. My own constituency has lost 65 square kilometres to coastal erosion since I became the MP. I have said in this House, and in a letter to the Prime Minister, if we had lost one inch to the Chinese, we would have made it a national issue. We have lost 65 kilometres to natural disasters we do not seem to care. I am sorry, Sir.

According to the All India Meteorological Department, 2024 has witnessed already a staggering 536 heatwave days, the highest in nearly 14 years, and between 2013 and 2022, heatwaves and sunstrokes claimed more than 10,000 lives and yet the Government obdurately refuses to acknowledge this disaster looming over us.

The Disaster Management Act was passed over nineteen years ago. It might not have anticipated that climate change would get so bad and that coastal erosion and heatwaves would transmogrify into such a formidable challenge in the future. But why not this Bill? If this Bill has learnt any lessons in the last nineteen years, it should show them here. Why could it not devise a mechanism to grapple with this burgeoning crisis? Though the Disaster Management Act?s definition of a disaster is actually broad enough to encompass climate-induced events, its statutory list remains static and unimaginative. It obstinately ignores the realities that our citizens are enduring. This is a dangerous oversight, as the impacts of such events ? widespread loss of life, destruction of livelihoods ? are no less severe than the devastation wrought by floods or earthquakes.

In failing to adapt, we risk exposure to avoidable calamities. The Government demonstrates its indifference to the plight of those numerous Indians who perished because of a heatstroke or lost their homes and livelihoods to coastal erosion. Therefore, the NDMA needs to enhance its capacity to prevent climate change from becoming disasters, such as unprecedented landslides in Wayanad?s case, heat waves, and storms. Let us not forget that among the primary contributors to the Wayanad calamity were a host of issues, not just excessive rainfall as the Home Minister has mentioned. These were, widespread deforestation, with 62 per cent of Wayanad?s forests having disappeared since 1950; ceaseless soil erosion, made more relentless by rainwater seeping into loose topsoil, which reduces soil cohesion and contributes to landslides; and soil piping: the formation of underground tunnels because of subsurface soil erosion. The fact that I want to say very simply is that climate change is worsening the situation,

especially with more flash floods and landslips being triggered by merciless and ruthless monsoons.

With the warming of the Arabian Sea creating deep cloud systems, which result in brief spells of ruthlessly intense rainfall, Kerala will be yet more vulnerable to landslides. We must take stock of these facts, uncomfortable though they may be and seek to confront them head on. ? (*Interruptions*) Sir, I will wrap up. I just need two minutes for one last point. We wanted this Bill. We wanted it to be imaginative and innovative. But we have seen none of that. We have not seen financial and administrative preparedness. Instead, it is just a testament of the Government?s insistence to rush it through Parliament. But let me ask the hon. Minister in all earnestness: What good will bulldozing this Bill through Parliament do if it cannot prevent another Wayanad? Where are the provisions for disaster prevention, like landslide-mapping and coastal protection measures? It will not do India and Indians any good merely to create a framework that does not actually devolve any powers upon the States, upon local urban bodies, upon self-government units in our country. What is needed is a stricter streamlining of a scattered policy framework that has far too many authorities and bureaucratic muddles, an end to the concentration of powers in the Centre?s hands, and a genuine attempt to learn from our failures at navigating past disasters and keeping up with the challenging realities of our climate change.

A revised Bill should allow for expertise independent of committees, streamline and clarify the role of each of the newly introduced bodies ? (*Interruptions*) and give the MPs a right to be heard. ? (*Interruptions*) I am just finishing. It should make disaster relief a legal right, and revive the Parliamentary Forum on Disaster Management to give the MPs? views a chance to be heard. This Bill does not have any of these qualities. Therefore, it must be returned to the drawing board. And I urge the Minister to withdraw the Bill.

Thank you very much. Jai Hind.

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (हरिद्वार) : सभापति महोदय, आज मैं आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 और उत्तराखंड में बार-बार आने वाली आपदाओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि यह विधेयक शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और और राज्य की राजधानियों में यूडीएमए स्थापित करने का प्रस्ताव करता है । यह एक नई अवधारणा है और निश्चित रूप से यह बहुत कारगर साबित होगी । जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं या आपदा से पहले जो आवश्यक प्रबंधन करने होते हैं, उसे करने में यह सफल होगा । इसमें राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटा बेस का प्रावधान किया गया है जो 72 जोखिम आंकलन और संसाधन आबंटन में मदद करेगा ।

तीसरा विषय यह है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, एसडीआरएफ का गठन, राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों को तैनात करने की अनुमति देगा । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं । निश्चित रूप से राज्यों में इनकी तैनाती की अनुमति देने से पूरे देश के राज्यों को इसका लाभ होगा । विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर या पूर्वोत्तर के राज्य हों, वहां पर आपदा प्रभावित स्थल अक्सर बहुत दुर्गम होते हैं । जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो कई बार वहां की नेटवर्क भी प्रभावित होती है । वहां सड़कें टूट-फूट जाती हैं, उन पर आना-जाना मुश्किल हो जाता है । उस समय वहां हवाई सेवाएं भी बाधित हो जाती हैं । ऐसे में जोखिमों का आंकलन और आपदा डेटा बेस के आधार पर संसाधन आबंटन करने में निश्चित रूप से प्रतिक्रिया बल को मदद मिलेगी ।

जो शहरी योजना का प्रावधान किया गया है, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर योजनाओं को तैयार करेगा और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा । इसमें व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण किया गया है । मैं समझता हूं कि इन्हें विकेंद्रीत करने से अधिकतम समाजिक संगठन, प्रतिक्रिया बल को इसमें इंवॉल्व करके जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, स्थानीय आधार पर जो स्थानीय आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उसे ध्यान में ही रख कर आगे योजना बनाई जाएगी और प्रभावित लोगों को उससे मदद मिलेगी ।

मैं जलवायु परिवर्तन और जोखिमों के आंकलन के बारे में कहना चाहता हूं कि विधेयक जलवायु से जुड़े खतरों का नियमित मूल्यांकन करने पर जोर देता है, जिससे जलवायु प्रेरित आपदाओं जैसे ग्लेशियर, लेक्स का फटना, फ्लड्स और अनियमित मौसम पैटर्न के लिए बेहतर तैयारी की जा सकेगी । आज इस तरह की परिस्थितियाँ का निर्माण हो रहा है । आज कहीं न कहीं देश और दुनिया यह महसूस कर रही है कि इको-सिस्टम में कुछ परिवर्तन आ रहा है । मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है । ऐसी परिस्थितियों में ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उनसे समय पूर्व आंकलन करने में सुविधा होगी । प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी एवं इसमें एआई के इस्तेमाल करने की जो बात है, उससे दुर्गम क्षेत्र में, जहां पर अकस्मात आपदाएं आती हैं ।

उनका कई बार पता भी नहीं चल पाता है और उससे बचने के लिए बहुत कठिनाई होती थी । उसमें एआई का इस्तेमाल करके चेतावनी प्रणाली विकसित की जा रही है । उससे समय पूर्व जब चेतावनी दी जाएगी तो उससे जो जान-माल का खतरा है, वह बच सकेगा । पुनर्वास के बजाय पुनर्प्राप्ति सहायता ? यह एक महत्वपूर्ण सुधार है । जो आपदा पीड़ित हैं, उनकी सहायता के लिए बहुत ही सकारात्मक सुधार किया गया है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो आपदा है, इसके कारण नौनिहाल, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में हैं, उनका जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है । विशेषकर नौनिहालों का जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि आपदा के समय विस्थापन अनिवार्य हो जाता है । हम जहां पर विस्थापन करते हैं, वहां पर उनकी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल है, वह प्रभावित होता है । अगर हम यूनिसेफ के आंकड़े पढ़ेंगे तो वे बहुत चौंकाने वाले हैं । पिछले दस सालों में लगभग 3 करोड़ 70 लाख बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं । उनका जो मानसिक विकास है, वह प्रभावित हुआ है और उनका शारीरिक विकास प्रभावित हुआ है । उनके परिवार का आर्थिक ढांचा, आर्थिक स्वरूप भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है । ऐसे में जो प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं, जो सुधार इसमें किए गए हैं, मैं समझता हूं कि उससे निश्चित रूप से नौनिहालों को या हम यह कहें कि जो देश का भविष्य है, भावी भारत है, उससे भारत सुदृढ़ होगा । वे बच्चे देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभा सकेंगे । इसी तरह से जब आपदाएं आती हैं, तो हमारे जो वन्य जीव हैं, वन सम्पदा है, वह बहुत ज्यादा प्रभावित होती है । जो वन सम्पदा है, वन्य जीव हैं, इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है और उसमें भी इस बिल के कारण कुछ सुधार आएगा ।

महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल हैं । उनका जो सीमांत क्षेत्र है, वहां पर एक क्वारी गांव है । क्वारी गांव धंसाव पर है । ग्लेशियर से जो पिंडर नदी निकलती है, उसमें दो साल तक पानी में मिट्टी बहकर आती रही । वहां के जो जलीय जीव हैं, वे प्रभावित हुए हैं । उसके कारण उसके जीवन पर संकट आया है । यह आपदा केवल क्षणिक नहीं होती, बल्कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर नाप भूमि है, उसके अलावा जो भूमि है, वह वन भूमि है । वन भूमि होने के कारण जब उनके विस्थापन की जरूरत होती है, उनको विस्थापित किया जाता है तो उनको विस्थापित करने में भूमि का भारी अभाव होता है । उसके कारण कई बार हम उन्हें स्कूलों में ठहराते हैं, पंचायत भवनों में ठहराते हैं । हमारी जो शिक्षा है, उसके कारण वह भी प्रभावित होती है, क्योंकि पहाड़ों में ढालधार खेत है । ऐसे में वहां पर उनके लिए टेम्परेरी व्यवस्था करने में भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है । लोगों में एक तरह से भय का वातावरण बना रहता है । जो प्रभावित लोग हैं, उनका क्षेत्र चाहे कितना ही प्रभावित हुआ हो, वह अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता है । वह अपने गांव में ही रहना चाहता है, क्योंकि उसकी जो आजीविका का स्रोत है, उनकी जो खेती है, उसे बाहर खेत नहीं मिल सकते हैं और न ही उनके लिए उपलब्धतता होती है । इस अमेंडमेंट बिल में जो चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की गई है, एआई का सहारा लिया गया है, मैं समझता हूं कि उसके कारण इसमें तमाम तरह की सुविधाएं होंगी ।

उत्तराखण्ड एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ पर बरसात के दिनों में भारी भू-स्खलन और लैंड इरोज़न होता है । वहाँ की उपजाऊ मिट्टी बहकर नालों में, नालों से नदियों में और नदियों के माध्यम से नीचे मैदानी भागों में चली जाती है और उसको उपजाऊ करती है । लेकिन वहाँ की उपजाऊ मिट्टी उससे प्रभावित होती है । मिट्टी में जो तमाम तरह के मिनरल्स होते हैं, उनका वहाँ पर अभाव होता है । वहाँ पर सामान्यत: ऑर्गेनिक खेती होती है और उससे हमारी खेती प्रभावित होती है । इसके साथ ही, उससे हमारा स्वास्थ भी प्रभावित होता है । एक उम्दा, एक स्वास्थ्यवर्धक अनाज के उत्पादन में स्वाभाविक रूप से कमी आती है । उससे जन-धन, पशुधन आदि सारी चीजें प्रभावित होती हैं । मैं समझता हूँ कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी के द्वारा जो अमेंडमेंट प्रस्ताव रखा गया है, उससे निश्चित रूप से इन सब चीजों में मदद हो सकेगी । इन सारी चीजों का जो सोशियो-इकोनॉमी इफेक्ट पड़ता है, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी ।

माननीय सभापति जी, मैं उत्तराखण्ड के संबंध में कुछ और बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । हमारी अधिसंख्य नदियाँ हिमालय से निकलती हैं । आज जो ग्लेसियर्स हैं, वे प्रभावित हो रहे हैं । वर्ष 2013 में केदारनाथ ऊपर जो चोराबाड़ी ताल था, जिसको गांधी सागर ताल भी कहा जाता है क्योंकि गांधी जी की अस्थियाँ वहाँ पर प्रवाहित की गई थी, इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं । वह टूट गया । इसके कारण केदारनाथ जैसी आपदा आई, जिसमें लगभग 10 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई । उस समय मौसम इतना खराब था कि वहाँ पर पहुंचना मुश्किल था क्योंकि तमाम रास्ते ध्वस्त हो गए थे, जिसके कारण वहाँ पर पहुंचना काफी कठिन था । मुझे याद है, हमारे प्रधानमंत्री जी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे । वे केदारनाथ की आपदा में सहायता करने के लिए वहाँ से सहायता का प्रस्ताव लेकर उत्तराखण्ड आए थे । चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनको वहाँ उतरने की परमिशन नहीं दी गई, तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और लगभग डेढ़ दिन वे उत्तराखण्ड में रहे । उस समय उन्होंने उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्ताव दिया था कि केदारनाथ मन्दिर के पुनर्निर्माण का काम है, जो मन्दिर ध्वस्त हो गया है, उसके पुनर्निर्माण का काम गुजरात करेगा । दुर्भाग्य से, तत्कालीन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाबा केदार के आशीर्वाद से उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण किया । आज वहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं । देश भर से जो श्रद्धालुगण आते हैं, उनके लिए बेहतर सुविधाएं दीं । यही नहीं, बदरीनाथ जी में भी मास्टर प्लान के तहत

पुनर्निर्माण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की आपदा को, वहाँ की पीड़ा को समझा । उन्होंने उस समय गुजरात से स्पेशल ट्रेन सहायता लेकर भेजी थी । उत्तराखण्ड के लोग इसको कभी नहीं भूल सकते हैं । ऐसी आपदा के समय में, जब वे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस संवदेनशीलता से उत्तराखण्ड के लिए काम किया, जितनी तत्परता से वे उत्तराखण्ड के लोगों के साथ खड़े नज़र आए, आज उत्तराखण्ड के लोग उनके साथ उसी तरह से खड़े नज़र आ रहे हैं और आगे भी साथ खड़े नज़र आते रहेंगे ।

माननीय सभापति जी, मैं कुछ और विषयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । मैं समझता हूँ कि जिस पर बहुत अधिक गम्भीरता से ध्यान देने की जरूरत है, वह है अवैज्ञानिक तरीके से माफिया तत्त्व खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है, जिससे हमारे जलस्रोत प्रभावित हो रहे हैं । इसके साथ लगे हुए किसानों के खेत भी उससे प्रभावित होते हैं । पानी का तल लगातार नीचे जा रहा है ।

इसलिए, इस तरह की जो आपदाएं हैं, उनसे भारी नुकसान होता है । मेरा लोक सभा क्षेत्र हरिद्वार है । हरिद्वार में पिछले वर्ष की जो बरसात थी । ? (व्यवधान) धन्यवाद, आप भी हरिद्वार से हैं । ? (व्यवधान) जब भारी बरसात हुई, तो उसके कारण हरिद्वार जनपद की जो शुगर मिल्स हैं, वहां तीन शुगर मिल्स हैं, वहां 60 परसेंट गन्ने की खेती पानी में डूब गई । उसके कारण 40 परसेंट पर ही वहां की शुगर मिल्स ने काम किया । मैं उदाहरण देकर इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नदियों के कारण और भारी बरसात के कारण ऐसा हुआ । उस समय गंगा जी का जो करंट होता है, वह बिजली की तरह होता है, उसकी इतनी गति होती है । वह पानी खेतों में चला जाता है । जो गंगा और फौलानी नदियां हैं, उनसे वहां के किसानों की खेती की सुरक्षा के लिए इन तटों को बांधना भी बहुत जरूरी है, ताकि किसानों का जो नुकसान होता है, उस नुकसान से बचा जा सके । इस आपदा से किसानों को राहत मिल सके । उस समय मैं वहां का जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वहां जनप्रतिनिधियों का जाना बहुत मुश्किल हो गया, लोग गुस्से में थे, क्योंकि उनकी आय का जो सोर्स है, जो उनकी इनकम का मुख्य सोर्स है, उनके परिवारों को चलाने का जो मुख्य अधार है, जो कि खेती है, वह उससे प्रभावित हुई । इसलिए, आपदा प्रबंधन से पूर्व जो आकलन होते हैं, इस तरह के जो अनुभव आते हैं, उनसे बचाव के लिए इन नदियों को बांधा जाना बहुत जरूरी है । उनके तटों को मजबूत तटबंधों के द्वारा बांधा जाए, ताकि किसानों की खेती को बचाया जा सके । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, उत्तराखंड में तमाम भूकंपीय आपदाएं आती हैं । हमने देखा है कि वर्ष 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप आया, उसके बाद चमोली में भूकंप आया, क्योंकि उत्तराखंड एमसीटी ? मेन सेंट्रल थ्रस्ट पर है । उसकी लंबाई जितनी हिमालय की लंबाई है, लगभग ढाई हजार किलोमीटर है । उस सेंट्रल थ्रस्ट पर उत्तराखंड और तमाम हिमालयी राज्य रहते हैं । वहां लोग निवास करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग वहां पर, उन स्थानों पर अपने घर बना लेते हैं, अपनी दुकानें बना लेते हैं और बाकी सब व्यवस्था कर लेते हैं ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एमसीटी के बारे में लोगों को बताया जाए । उस इलाके में जो मानवीय बसावट है, उसके लिए कोई न कोई, ऐसी टैक्नोलॉजी हम उनको दें कि उसी टैक्नोलॉजी से वहां पर निर्माण किया जाए । वहां जहां ज्यादा खतरा बार-बार महसूस होता है, उसको प्रतिबंधित किया जाए । जैसा जोशीमठ में पिछले साल हुआ, उस तरह की दिक्कतें सामने न आएं, क्योंकि वह पूरा हिमालयी क्षेत्र है और मोरेन पर बसा हुआ है । पूरी लैंड अलखनंदा की तरफ लैंडस्लाइड कर रही है । इसी तरह की पूरी वह बैल्ट है, जैसे जोशीमठ है, वहां से उत्तरकाशी का भटवाड़ी जिला है । ऐसे ही अगर नौ किलोमीटर का पैच छोड़ दिया जाए, तो उत्तर-पूर्व की ओर और उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 2,500 किलोमीटर

लंबी यह बैल्ट है । इस पर हमको समय-समय पर वहां के लोगों को जागरुक करना होगा । वहां की राज्य सरकारें उससे लोगों को जागरुक करें, अवेयर करें, ताकि जो मानव क्षति है, जो पशुधन की क्षति है, जो खेती की क्षति है, उसको हम लोग न्यून कर सकें ।

मुझे लगता है कि अवेयरनेस के लिए, जागरुकता के लिए इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे निश्चित रूप से लोग जागरुक होंगे । जिस तरह से आपदा मित्र बनाए जा रहे हैं, उन आपदा मित्रों के माध्यम से जागरुकता का कार्य होगा । किसी भी आपदा की स्थिति में स्वाभाविक रूप से वहां के स्थानीय लोग सहायता के लिए पहुंचते हैं । इसलिए, आपदा मित्र बनाने की जो योजना माननीय गृह मंत्री जी ने तैयार की है, निश्चित रूप से इन आपदा मित्रों के माध्यम से हम आपदा के कारण जो तमाम तरह के नुकसान होते हैं, उनको नियंत्रित करने में, उनको कम करने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है ।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, which was introduced in the Lok Sabha. I would first speak about certain positive changes that have been brought by the Government through this Bill.

First of all, the Director General of Police is now made the ex-officio member of the State Executive Committee by insertion of clause (c) in sub-section (2) of Section 20. This is a positive change as an officer of police force of the State shall now have an active role in laying policy for disaster management and response.

Then, the Bill also seeks to create the Urban Disaster Management Authority for State Capitals and municipal corporation areas by introducing Section 41A in the Principal Act. This is also a positive change for the State. The State is empowered to constitute a State Disaster Response Force by insertion of Section 44 (a) in the Principal Act of 2005.

Sir, there are certain parts of the Bill where no effective changes have been brought, like, Section 19 of the Principal Act of 2005, which is omitted. That speaks about the guidelines for minimum standard of relief to persons affected by disasters in the State. The same power has been given under Section 18 (2)(o) of this Act of 2005. Hence, no effective changes are done.

The functions of the State Executive Committee given under Clauses (a), (c), (i), (k) and (n) of sub-section (2) of Section 22 of the Principal Act of 2005 are omitted. These powers along with the power of maintaining State disaster database are now given to the State Authority instead of State Executive Committee by introduction

of clause (i) to (iii) in sub-section (2) of Section 18 of the Principal Act of 2005. It is not an effective change at all.

There are some negative changes also in the new Bill. An explanation has been inserted in Section 2 clause (d) to clarify the expression ?man made causes?. It does not include any law and order related matter or situation, or any situation arising from a law and order related matter or situation.

What is the probable implication? Payment or relief for loss of life or damage to property in any riot-like situation may not be possible.

Then, a new clause (u) has been inserted in Section 6 (2), whereby the National Authority may undertake in the aftermath of severe disasters in any State, post-disaster audit of preparedness and response activities of the State.

What is the probable implication of this? The possibility of misuse of this clause against the State Government cannot be ruled out.

In Section 56, a new sub-section (2), has been inserted by which the State Government has been mandated to take disciplinary action on its own or on the direction of the Central Government against an officer who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office on grounds of insubordination or dereliction of duty during a disaster. The action taken by the State Government shall not be inconsistent with the directions given by the Central Government.

What is the probable implication of this? It appears to be an attempt to give authority to the Central Government to control the action of the officers of the State Government. This provision encroaches upon the authority of the State Government thereby destroying the federal structure of the Constitution. Here, possibility of misuse against the State Government cannot be ruled out.

Then, a new Section 41A has been inserted for creation of separate Urban Disaster Management Authority for the State Capitals and all cities having a municipal corporation. In such UDMAs, the Municipal Commissioner has been made Chairperson, ex-officio, and the District Collector of the district has been made Vice-Chairperson. Now, what is the possible probable implication? In some cases, like Bidhannagar Municipal Corporation or Asansol Municipal Corporation, this may create hierarchical anomaly as the Collector may be senior to the Municipal Commissioner.

Sir, India stands on the cusp of being the world?s third largest economy. It is already the most populous nation. In India, despite the constitutionalisation of functions of municipalities, the total municipal expenditure accounts for hardly 0.79 per cent of the GDP. In the post-World War years, Japan spent six to eight per cent of its GDP on an average on disaster management efforts, resulting in the country becoming one of the global leaders. But this Bill does not adequately address the resource and the funding gaps at the local level, particularly in setting up of and maintaining UDMAs.

The new disaster management builds on the provision seeking to institutionalise a similar response team at the State level to be called State Disaster Response Force and also to constitute a separate Urban Disaster Management Authority for the State Capitals and for all cities having municipal corporations, barring Delhi and Chandigarh, to bring in an extra layer of city level disaster management institution.

The removal of usage guidelines for the National Disaster Response Fund also raises concerns about centralised control over the Fund. Following the amendments, the National Executive Committee and the State Executive Committee will no longer formulate national-level and State-level disaster response. The NDMA and the SDMAs would take over this duty in lieu of empowering the local authorities with greater autonomy and resources for disaster response. That gives the Central Government more power to make decision which could reduce the independence of the State and the local authorities, and will solve more problems than it solves.

This Bill practically does not speak anything about the cooperative federalism; it is rather destroying the structure of federalism. Ultimately, whenever the disaster takes places, who are the primary persons who will come and take the responsibility? They are the officers of the State. We can see it for the last ten years that Bill after Bill is being brought and a good attempt has been made in this country to destroy the federal structure of the country.

India, with 2.4 per cent of the world?s land, houses about 17.78 per cent of the global population. It induces pressure on resources and competition over fragile ecosystem which, in turn, increases the risk of disasters. The traditional role that the welfare State plays in India in providing disaster relief is that of obligatory nature, which has not been extended as a legal right. Mr. Tharoor was talking about the Fundamental Right. Of course, the question of Fundamental Right comes up when a person faces a disaster. Leave aside this Fundamental Right, why should

the legal right not be created? Of course, it comes under Article 21 of the Constitution, but a legal right has to be created for those who are suffering.

15.53 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

Basically, this Bill has no such mechanism that allows collaboration among various stakeholders. Even this Bill does not adequately address the need of resources and expertise of the local authorities, especially in the smaller cities.

Despite the Disaster Management Act, 2005 being there over the last two decades, the national guidelines for minimum standards of relief have not empowered the States for moral or obligatory framework to empower its citizens to claim certain minimum relief through a coordination process and to make it legally obligatory for the States to disburse the relief timely and effectively. This Bill also has no further clarity on how to achieve such coordination in practice among a diverse set of institutions, including non-government, private and general public.

The Bill shows much evidence of a further centralisation of an already heavily Centralised Disaster Management Act. The Act, in its current form, already mandates the creation of many authorities and committees at the national, State and district levels. The proposed Bill further provides statutory status to the existing organisations such as the National Crisis Management Committee and High Level Committees, complicating the chain of action to be followed in cases of disaster. There are so many cases. Who will take the decision? Who will do it? Who will perform the duty?

The Bill empowers the NDMA to take stock of the entire range of disaster risks, including fresh disasters that the country could face. Hence, through a process of centralization of power, this Bill is seriously going to blur the lines of responsibility among various levels of Government and while scrutiny over its constitutionality as disaster management is not explicitly mentioned in the Constitution?s Concurrent List, a proper entry could be inserted to cover the issue of disaster management.

Today, there are 268 Municipal Corporations in India. Setting up of UDMAs means that regarding disasters, the Municipal Corporations would be managed by UDMAs and would no longer be part of the Disaster Management Authority. The UDMA, as a consequence, would be headed by the Municipal Commissioner, as the Chairman with the Collector as Vice-Chairman, irrespective of age and authority, and will directly be overseen by the Central Government. But it has not been clear how it will coordinate with fire, transportation, and water services, which are under the

jurisdiction of the State, and the law and order machinery throughout the country is controlled by the State.

Sir, I know that Mrs. Sarangi will, of course, oppose this. Now, the Collector has gone down. The Municipal Commissioner will be above him or her. I will be waiting to hear what is the response of Mrs. Sarangi so far as this part is concerned. The point of worry is that while the Municipal Corporations are endowed with greater disaster management authority in relation to the geographies under their control, they may be thwarted by minimal overall powers and sources.

Sir, the local Governments have also been observed to play a key role in coordinating responses to extreme climate events and other disasters. Different research organizations affirm that while outcomes are uneven, vesting powers and resources with local authorities leads to gains in a wide variety of State functions relating to public service delivery, rural development, and the delivery of social security mechanism.

Now, I will come to proactive measures. Many State Governments such as Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, basically from Kashmir to Kerala and Maharashtra to Manipur, took proactive measures to contain the spread of COVID-19, including lockdowns, curfews, and total restrictions, including relief packages and free rations for the poor and shelter for migrants. There was effective testing and contact tracing. The States like Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal ramped up testing and contact tracing efforts to identify and isolate infected individuals. There were economic relief packages. Several State Governments announced economic relief packages, including financial assistance to daily wage workers, farmers, and small business owners. There was community engagement. The State Governments engaged with local communities, NGOs, and voluntary groups to promote awareness, provide support, and facilitate relief efforts. The State Governments set up dedicated COVID-19 hospitals and quarantine centres to provide medical care and isolate infected patients.

Coming to vaccination drives, the State Governments organized vaccination drives. Some States even offered free vaccination to their citizens. For the last two or three years, we can only hear that the Central Government has done this. मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है । अरे! हम लोगों के स्टेट में किसने किया है? आपके स्टेट में कौन किया है? वह हम लोग भी करते हैं । जब हम लोग करते हैं, तब आप क्रेडिट ले लेते हैं । ? (व्यवधान) Sir, unfortunately, for these expenses, the Central Government has not paid anything.

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, हमारे माननीय कल्याण बनर्जी जी शायद कोविड के समय ...* रहे होंगे । पूरी दुनिया को कोविड के समय माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में कितना सहयोग दिया गया, वैक्सीन दी गई । वहीं पश्चिम बंगाल ने और इनकी सरकार द्वारा केंद्र सरकार को उस समय परेशानी में डालने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करती थी । जो वैक्सीन जाती थी, उसको ट्रैफिक क्लियरेंस नहीं देते थे । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister, you have made your point.

श्री नित्यानन्द राय: आपदा के समय जो ट्रेन जा कर पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्टेशनों पर खाद्यान्न पहुंचाने के लिए रुकी रहती थी और ये तैयार नहीं होते थे । ? (व्यवधान) जब हम लोग तैयार होते थे तो ये लोग उसमें बाधा डालते थे । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak.

<u>16.00 hrs</u>

श्री नित्यानन्द राय: कोविड के समय सब लोगों ने मिलकर काम किया । हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसे स्वीकारते हैं ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please let him complete.

? (*Interruptions*)

श्री नित्यानन्द राय: यह हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है ।? (व्यवधान) इसे पूरी दुनिया ने सराहा है । आप क्या सवाल कर रहे हैं? ? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी **:** आप बैठिए । हम आपके विषय पर आते हैं ।? (व्यवधान) हम कोविड के बारे में बोलेंगे ।? (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: आप गलत मत बोलिए ।? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, this is the disturbance that ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, in any case the Minister is going to give reply. At that time, it can be covered.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please continue.

? (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, हिन्दी में एक गाना है, क्या आप जानते हैं? हिन्दी में एक गाना है- ?झूठ बोले कौआ काटे? । आज उनको ? ? (व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए । आप बोलने ही नहीं देते हैं । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Kalyan ji is saying, please.

? (*Interruptions*) ..

श्री नित्यानन्द राय: ? बोलने वाले को ? भी काटता है । ? (व्यवधान) ? बोलने वाले को ? भी काटेगा, ?भी काटेगा और ? होगा ।? (व्यवधान) ? बोलने वाले का ? होता है । ? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Let us come to the point.

HON. CHAIRPERSON: Okay, you have made your point.

? (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, कोविड-19 के समय ये लोग दिल्ली में बैठे थे । हम लोग एमपी हैं । हम लोग लोकल एरिया में रहते हैं ।? (व्यवधान) हम लोग कोविड पेशेंट को लेकर अस्पताल गए हैं ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, please address the Chair.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I am addressing you.

श्री नित्यानन्द राय: कोविड के समय नरेन्द्र मोदी जी के सहयोग और नेतृत्व पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है ।? (व्यवधान) अगर वह सवाल उठा रहे हैं तो उनको सुनना भी पड़ेगा ।

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, please.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Will you please allow me to speak? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will give direction to him, please.

? (*Interruptions*)

श्री नित्यानन्द राय: इनको वैक्सीन देने के लिए बराबर दबाव डालना पड़ता था कि आप हमारी वैक्सीन को लीजिए और लोगों को लगाइए । पश्चिम बंगाल के लोगों की जान बचाइए । तब भी ये लोग नहीं सुनते थे । ? (व्यवधान) हम लोगों को इतना इम्फोर्स करना पड़ा, तब जा कर इन लोगों ने वैक्सीन ली ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, if you are replying to each and every Member then and there, then ?

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, please address the Chair.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the point, Kalyan ji.

? (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, पश्चिम बंगाल के आदमी ने इतना सुना है, इसीलिए आप लोग 18 से घट कर 12 हो गए ।? (व्यवधान) आप बैठिए, हमारी बात सुन लीजिए ।? (व्यवधान)

Sir, they do not have a degree of courage. ? (*Interruptions*) They all speak … ? (*Interruptions*) What is this? ? (*Interruptions*)

श्री नित्यानन्द राय**:** आप लोगों को पश्चिम बंगाल के लोगों की जान की परवाह ही नही थी ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I request you to first take your seat.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, please confine yourself to the Bill. Allegations and counter-allegations politically is not fit for this place. Please address the Bill on merit.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am telling everyone including Scindia ji. If at all you are having any grievance over his speech, it is up to you when your time comes. Please wait for it. You can give comprehensive answer to them. Do not worry.

? (*Interruptions*)

संचार मंत्री**;** तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री **(**श्री ज्योतिरादित्य एम**.** सिंधिया**) :** सर, हम आपके निर्णय के साथ सहमत है । परंतु, इसका मतलब यह भी नहीं है कि सदन के पटल पर, यह सदन एक गंभीर लोकतांत्रिक प्रणाली का मंदिर है, सरासर ? बोला जाए, यह बिलकुल उचित नहीं है ।? (व्यवधान) केवल इस सदन के अंदर आवाज उठाकर अपनी आवाज सुनाने की कोशिश अगर कोई सदस्य करे और वह यह कोशिश करे कि ? को सच में परिवर्तित करे, यह संभव हो ही नहीं पाएगा । ? (व्यवधान) देश और विश्व की जनता जानती हैं कि भारत ने विश्वबंधू के रूप में पूरे विश्व की कोविड के समय मदद की है । केवल भारत की 140 करोड़ जनता के ही नहीं, बल्कि 200 करोड़ इंजेक्शन लगाए ।? (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता एकत्रित हो उठी थी और इनकी सरकार ने बंगाल में क्या ? था, इसे बंगाल की पूरी जनता जानती है ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

? (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, आप मेरी बात सुनिए ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, you were entitled to do what your Government did in West Bengal. Do not make some allegations against them.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: No, I am not making any allegation in what I am saying. ? (*Interruptions*) Now, two Ministers have made allegations against us. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

? (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, कोई मिनिस्टर बोले कि उनके पास पावर है । उनको पावर प्रोजेक्ट करके ? , यह भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता है ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I have to give answer to this. ? (*Interruptions*) because you are the Minister. ? (*Interruptions*) You are having power to raise your voice, to stand up and just to ...? (*Interruptions*) What is this? ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: This is not proper.? (*Interruptions*).

श्री ज्योतिरादित्य एम**.** सिंधिया **:** सर, आवाज कौन उठा रहा है? ? (व्यवधान) सर, किसके चेहरे पर ... है और किसके चेहरे पर मुस्कराहट है, आप स्वयं देख लें ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** आप सुन लीजिए । आप बहुत सुंदर दिखते हैं ।

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

श्री कल्याण बनर्जी **:** सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं तो यह नहीं है ... ऐसा कुछ नहीं है । ? (व्यवधान)

<u>16.05 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज माननीय सदस्य ।

? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी **:** आप देखने के लिए सुंदर हैं । आप बहुत बड़ी फेमिली से आते हैं । ? (व्यवधान) हमको छोटा करेंगे ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज, सब्जेक्ट पर आइए । ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूं । आप क्या सोचते हैं? सुंदर हैं तो सब कुछ हैं, ... ? आप क्या सोचते हैं? ? (व्यवधान) Do not do it.? (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य एम**.** सिंधिया **:** सर, इनके कमेंट पर मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं । इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है । ? (व्यवधान) सर, मेरा हक है जवाब देने का । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** क्या बोल रहे हैं?

श्री ज्योतिरादित्य एम**.** सिंधिया **:** सर, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है । मेरा जवाब देने का हक है । मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है । मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं । जो आज मैं हूं, जनता के आशीर्वाद, मेरी मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पर हूं । ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफिजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें । हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं । अगर ये बेफिजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है । आप विधेयक पर अपनी बात कहें । पर्सनल एक-दूसरे पर टिप्पणी न करें, न बैठे-बैठे करें, न खड़े होकर करें । आप अपने विषय पर बोलिए ।

SHRI KALYAN BANERJEE : He first attacked me personally. चेहरा ... गया है । आपके चेहरे में ब्यूटी है, तो जो मर्जी हो, वह बोल देंगे । हम आपके माफिक देखने में नहीं हैं तो क्या करेंगे भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत सुंदर हैं, आप ... हैं । वह सब हम जानते हैं ।? (व्यवधान) Why do you say that? हम बोल रहे हैं कि हम आपके माफिक सुंदर नहीं हैं । हम आपके माफिक रिच मैन नहीं हैं । क्या आप हमें जो मर्जी बोल लेंगे??(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

? (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया **:** सर, सदन की गरिमा के विरूद्ध कोई सांसद बोलेगा, तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे । ? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी **:** कोई गांव का आदमी इधर आया है और ... आप क्या सोचते हैं? देश के 140 करोड़ आदमी ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** कल्याण जी, टेम्परेचर डाउन ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी आप जवाब मत दीजिए । प्लीज बैठिए । मैंने उसको निकाल दिया है ।

? (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया **:** महिलाओं के प्रति इनका मान-सम्मान क्या है, यह दृष्टिकोण सदन के सामने आ गया है ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप अपना विषय खत्म करें ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** ये खत्म करने नहीं देते । दो मिनिस्टर उठकर बोलते हैं । I will not criticise the Central Government. I talked about the positive changes, they were silent. When I said that there is change, they are silent. The moment I started talking about the negative things, they are jumping. We will not allow this. I am coming from a middle-class family from the villages.

माननीय अध्यक्ष **:** आप विषय पर आ जाएं ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** सर, सुन लीजिए । I have studied in a *pathshala* and a village school. I am coming from the grassroots. I do not belong to any ... जो मर्जी है, वह करो । I have a medium standard. ? (*Interruptions*) It does not mean ? (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया **:** अध्यक्ष महोदय, अगर ये व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो हम इनका भी सामना करेंगे, हम इनको बोलने नहीं देंगे ।

श्री कल्याण बनर्जी **:** क्या बोलने नहीं देंगे ।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया **:** बिल्कुल बोलने नहीं देंगे ? (व्यवधान) बिल्कुल बोलने नहीं देंगे । ... सदन के अंदर कुछ भी बोलेंगे ।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही में कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है । प्लीज ।

? (व्यवधान) ?

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है ।

-

16.10 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Forty Minutes past Sixteen of the Clock.

____

16.40 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Forty Minutes past Sixteen of the Clock.

(Shri A**.** Raja *in the Chair*)

16.40½ hrs

DISASTER MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2024-Contd.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kalyan Banerjee, please continue.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, firstly, I would say that I did not want to hurt anyone including Mr. Scindia. I am really sorry. ? (*Interruptions*) If I hurt ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : I am sorry. I said, I am sorry. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the Bill. Kalyan ji, please come to the Bill.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I did not want to hurt Mr. Scindia at all. ? (*Interruptions*) I am sorry for that.

Now, what I would like to talk about is the Centre?s response. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, one minute.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, Mr. Kalyan Banerjee has risen in this House and said that he is sorry. But I will say this.

We all come to this House with a spirit of contribution to the nation?s development. We come with a purity of heart. But we also come with a sense of self-respect. Any individual in his life will not stand compromised with his self-respect. Attack us on our policies. Attack us on our views. But if you get personal, certainly be prepared for the response. He has apologised. But, through you Sir, I would like to convey to him that I do not accept his apology for the personal attack that he has made not only on me but also on the women of India with the words that he has used. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let us put a full stop; please come to the Bill.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I have already said sorry.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That is settled between the two. Hon. Members, it is not fair on your part.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The matter was referred to the hon. Speaker. The hon. Speaker has made it clear that it has been settled between the two.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Coming to the vaccination drives, now in some of the States, including the State of West Bengal, organized vaccination drives are even being offered ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please, it has been settled by the Speaker.

? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : So many free vaccinations have been made available. I am now coming to the Central Government?s response so far as COVID-19 is concerned.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned till five o?clock.

16.43 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

________-

-

17.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the Clock.

(Shri A. Raja *in the Chair*)

-

DISASTER MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2024-Contd.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ram Shiromani Verma.

? (*Interruptions*)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, आपने मुझे आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please resume your seats.

? (*Interruptions*)

श्री राम शिरोमणि वर्मा : महोदय, आज यह जो संशोधन बिल माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the issue was settled by the hon. Speaker. Now, a new speaker is speaking. Are you ready to hear it?

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are in the Treasury Benches. The entire country is watching you.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are in the Treasury Benches. That matter has been settled by the hon. Speaker. This is not fair on your part. Please.

? (*Interruptions*)

श्री राम शिरोमणि वर्मा : महोदय, इसमें एक तरफ?.? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please resume your seats.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House is adjourned till tomorrow at 11 o?clock.

17.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, December 12, 2024/ Agrahayana 21, 1946 (Saka)

________-

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in Lok Sabha (Seventeenth Edition)

* The sign **+** marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member**.**

** English translation of the speech originally delivered in Kannada.

* Moved with the recommendation of the President.

Expunged as ordered by the Chair.